डी एम भारती

बनाम

एल. एम. सूद और अन्य

सितंबर 19,1990

[न्यायाधिपति एस. रंगनाथन और न्यायाधिपति ए. एम. अहमदी]

सेवा कानून: बॉम्बे नगर निगम - एक प्रतिष्ठान से 10 अन्य में प्रतिनियुक्ति - प्रतिनियुक्त प्रतिष्ठान में प्राप्त पदोन्नति - प्रत्यावर्तन पर, क्या मूल विभाग में उच्च पदों के लिए कोई अधिकार प्रदान करता है।

अपीलकर्ता को 1955 में नगर निगम में एक ट्रेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1957 में एक टाउन प्लानिंग अधिकारी की नियुक्ति के साथ, अपीलकर्ता को टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में एक ट्रेसर के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में, टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन का पद खाली हो गया। प्रतिवादी संख्या 6 को रिक्ति को भरने के लिए तैनात किया गया था। हालाँकि, इसके तुरंत बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई और अपीलकर्ता को 4.12.1959 से जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया।

सर्वेयर-कम-ड्राफ्ट्समैन का अगला उच्च पद खाली हो गया। इस बीच, 1962 में अपीलकर्ता को निलंबित कर दिया गया। औद्योगिक न्यायालय

ने उन्हें सेवा से हटाने की मंजूरी दे दी, लेकिन सुझाव दिया कि उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है। तदनुसार, अपीलकर्ता को नगर निगम के संपदा विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नए सिरे से नियुक्त किया गया, जहां वह पहले कार्यरत था।

व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए औद्योगिक न्यायालय को भेज दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध नियोक्ता अर्थात नगर निगम द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

औद्योगिक न्यायालय ने मामले की दोबारा सुनवाई की और अपीलकर्ता को सेवा से हटाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अपीलकर्ता को टाउन प्लानिंग एस्टेब्लिशमेंट में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया था, और उसे जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नहीं, बल्कि ट्रेसर के रूप में म्यूफिसिपल कॉर्पोरेशन की सेवा में वापस कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सीधी भर्ती वाले पहले से ही जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम कर रहे थे और ऐसी कोई रिक्ति नहीं थी जिसके खिलाफ अपीलकर्ता को नियुक्त किया जा सके।

अपीलकर्ता ने रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया। यह तर्क देते हुए कि चूंकि उन्हें टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें नगर निगम में निचले पद, जैसे ट्रेसर, पर वापस नहीं भेजा जा सकता था। यह भी तर्क दिया गया था कि डिप्टी म्यूनिसिपल कॉर्नमिशनर, पद से निचले पद पर थे। नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात नगर आयुक्त और इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था।

उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि अपीलकर्ता नगर निगम से टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्ति पर था और रिट याचिका खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा उसकी रिट याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है।

इस अदालत ने अपील खारिज कर दी और अभिनिर्धारित किया-

1..1 अपीलकर्ता की जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नति और नगर नियोजन प्रतिष्ठान में सर्वेयर-सह-ड्राफ्ट्समैन के रूप में प्रस्तावित पदोन्नति उन्हें उनके मूल विभाग में कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकती है। जब उन्होंने नगर निगम छोड़ा और टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में शामिल हुए तो वह एक ट्रेसर थे और वह संशोधन के अधीन, संपत्ति विभाग या नगर निगम के किसी अन्य विभाग में केवल अपने मूल पद यानी ट्रेसर के रूप में वापस जा सकते हैं। यदि इस बीच उसने किसी उच्च पद पर

पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है तो उसे उस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

1.2 दिनांक 16.8.1965 का आदेश औद्योगिक न्यायालय की अनुशंसा के अनुसरण में पारित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को हटाने की मंजूरी दी गई थी, ताकि उसकी नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जा सके। औद्योगिक न्यायालय के इस आदेश के मद्देनजर, अपीलकर्ता को एक पोस्टिंग दी जानी थी और चूँकि जब वह जूनियर ड्राफ्ट्समैन था, तब उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया। इसे फिर से नई नियुक्ति के आदेश के रूप में बनाया गया और अपीलकर्ता का यह अभ्यावेदन कि उसे वरिष्ठता दी जानी चाहिए, उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा यह भी तथ्य है कि अपीलकर्ता को 1 अक्टूबर, 1967 से इस पद से मुक्त कर दिया गया था। जाहिर तौर पर इस आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा, जब याचिकाकर्ता टाउनप्लानिंग प्रतिष्ठान में अपने पद पर बहाल हो गया तो इन आदेशों ने अपना आधार खो दिया। इन परिस्थितियों में दिनांक 16.8.65 के आदेश या 1966 में उनकी वरिष्ठता के निर्धारण का वर्तमान मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

2.1 अपीलकर्ता वास्तव में जो प्रयास कर रहा है वह उत्तरदाताओं 6 से 11 की नियुक्तियों को चुनौती देना है, जो कि उपरोक्त चयनों और नियुक्तियों के एक दशक से अधिक समय बाद 1978 में दायर एक रिट याचिका द्वारा

1963-64 में की गई थी। यह सच है कि, उस समय अपीलकर्ता संदेह के घेरे में था क्योंकि उसे निलंबित कर दिया गया था और बाद में सेवा से हटा दिया गया था। लेकिन फिर भी, अगर वह उन नियुक्तियों को चुनौती देना चाहते थे, तो उन्हें तत्काल कदम उठाने चाहिए थे। किसी भी तरह, ये बाधाएँ तब दूर हो गई थीं जब ट्रिब्यूनल ने, उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड पर, दिनांक 13.5.1964 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से हटाने को अस्वीकार कर दिया था। कम से कम 1971 में, जब उन्हें टाउनप्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पर बहाल करने का आदेश पारित किया गया था, तो उन्हें मूल विभाग में "प्रो-फॉर्मा" पदोन्नति प्राप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए था। तथ्य यह है कि उन्होंने 1963-64 से 15.2.1978 तक उत्तरदाताओं 6 से 11 की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। जब उन्होंने रिट याचिका दायर की या कम से कम 1.10.1976 तक, जब उन्होंने प्रत्यावर्तन आदेश के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया।

2.2 नगरपालिका अधिनियम की धारा 54(2) कर्मचारी चयन समिति को उस स्थिति से छूट देती है जब नियुक्ति पहले से ही नगरपालिका सेवा में मौजूद व्यक्तियों में से भरने का प्रस्ताव हो। लेकिन जो भर्ती हुई उसका स्वरूप ज्ञात नहीं है। इसके अलावा, चयन पर निर्णय लेने के लिए कर्मचारी चयन समिति का गठन अवैध नहीं कहा जा सकता है, भले ही यह स्थिति में अनिवार्य न हो। उच्च न्यायालय ने पाया है कि कर्मचारी चयन समिति

द्वारा उचित जांच के बाद उत्तरदाताओं 6 से 11 को सीधे जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में चुना गया था। माना जाता है कि इन नियुक्तियों और चयनों के संबंध में नगर निगम कर्मचारियों के बीच एक परिपत्र था। अपीलकर्ता को उस समय चयन के लिए आवेदन करना चाहिए था या, यदि वह अधिक उचित समझता, तो कर्मचारी चयन समिति के गठन और सीधी भर्ती को चुनौती देनी चाहिए थी और अपनी वरिष्ठता के आधार पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नति के लिए अपना दावा पेश करना चाहिए था। वह महत्वपूर्ण समय पर ऐसा करने में विफल रहे। ऐसा हो सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निलंबन और उसके बाद सेवा से निष्कासन के कारण उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 1971 में, उनके निलंबन और निष्कासन के मूल आदेश को रद्द कर दिए जाने के बाद भी, उन्होंने मूल विभाग में अपने अधिकारों का दावा करने के लिए तत्काल कोई कदम नहीं उठाया। वह स्पष्ट रूप से टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में अपनी बहाली से संतुष्ट थे। उत्तरदाताओं 6 से 11 की नियुक्ति की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता उनके मुकाबले किसी भी पदोन्नति का हकदार नहीं था और वह जूनियर के रूप में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। ड्राफ्ट्समैन जब 1976 में ऐसा कोई पद नहीं था जिस पर उन्हें नियुक्त किया जा सके।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 1213 / 1979

1978 के एल.पी.ए. संख्या 97 में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.4.1978 से।

अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

उत्तरदाताओं के लिए एच.एस. परिहार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधिपति रंगनाथन :

अपीलकर्ता, डी.एम. भारती, अहमदाबाद शहर के नगर निगम के उप नगर आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 30.9.1976 के आदेश की वैधता को चुनौती देते हैं। उक्त आदेश के अनुसार उप नगर आयुक्त ने नगर नियोजन प्रतिष्ठान में कार्यरत नगर निगम के कर्मचारियों को नगर निगम में समाहित किये जाने के संबंध में निगम ने अपीलकर्ता को प्रतिष्ठान में कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के पद से "वापस" कर दिया और उसे निगम के नगर विकास विभाग में एक अनुरेखक के पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने उसकी रिट याचिका खारिज कर दी और इसलिए वर्तमान अपील खारिज कर दी।

प्रासंगिक तथ्यों को बताना आवश्यक है। अपीलकर्ता को 26.6.1955 को नगर निगम के संपदा विभाग में एक अनुरेखक के रूप में नियुक्त किया गया था और 18 फरवरी, 1957 तक वहां काम किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने प्रावधानों के तहत एक नगर नियोजन अधिकारी नियुक्त

किया था बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट 1954 की धारा 31। नगर नियोजन अधिकारी को एक प्रतिष्ठान उपलब्ध कराया जाना था। नगर नियोजन अधिकारी की स्थापना निश्चित रूप से अस्थायी थी। दोनों प्राधिकरणों के बीच एक व्यवस्था की गई कि योजना कार्यालय में मध्यस्थ अपनी स्थापना के लिए निगम से ऐसे व्यक्तियों का चयन कर सकता है जैसा वह उचित समझे। नगर नियोजन अधिकारी ने अपीलकर्ता की सेवाओं की मांग की और उसे एक अनुरेखक के रूप में नियुक्त किया गया। 22.2.1957 को नगर नियोजन स्थापना। यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता वहां स्थानांतरण के माध्यम से गया था या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से क्योंकि 22.2.1957 का मूल आदेश हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, उच्च न्यायालय और अपीलकर्ता इस आधार पर आगे बढ़े कि अपीलकर्ता को नगर निगम से नगर नियोजन प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्त किया गया था।

कुछ समय बाद, टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन का पद खाली हो गया। अपीलकर्ता ने हमें बताया कि उन्हें 4.12.1959 को उस पद का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री येवला (डब्ल्यू.पी. में प्रतिवादी संख्या 6) को उस रिक्ति को भरने के लिए 21.4.1960 को तैनात किया गया था, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी और अपीलकर्ता को टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया था। 4.12.1959. अपीलकर्ता ने हमें बताया कि बाद में

उन्हें सर्वेयर-कम ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्ति के लिए भी सिफारिश की गई थी, जो एक उच्च पद था और जो 28.2.1962 को खाली हो गया था।

लेकिन इससे पहले कि यह प्रस्ताव अमल में आता अपीलकर्ता को 5 दिसंबर, 1962 को निगम द्वारा निलंबित कर दिया गया और 13.5.64 को सेवा से हटा दिया गया। औद्योगिक न्यायालय ने अपीलकर्ता को सेवा से हटाने की मंजूरी दे दी, लेकिन कुछ टिप्पणियां कीं जिससे पता चला कि वह फिर से हो सकता है। -उक्त पद पर नियुक्त किया गया। अपीलकर्ता ने औद्योगिक अदालत के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। अंततः उच्च न्यायालय ने 1.2.1969 को औद्योगिक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए औद्योगिक अदालत को भेज दिया। नगर निगम ने इस न्यायालय में एस.एल.पी.48/71 को प्राथमिकता दी जिसे 27.1.71 को खारिज कर दिया गया। औद्योगिक अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मामले की दोबारा सुनवाई की और अपीलकर्ता को सेवा से हटाने के आदेश को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.5.64 को हटाने का आदेश रद्द हो गया और 3.3.71 को एक आदेश पारित किया गया। नगर निगम आयुक्त द्वारा कि अपीलकर्ता को टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था।

इस बीच, 16.8.1965, औद्योगिक न्यायालय की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को नगर निगम के संपदा विभाग में जूनियर

ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वह पहले कार्यरत था। यह एक नई नियुक्ति बताई गई और इसलिए अपीलकर्ता ने एक अभ्यावेदन दिया कि उसे उसकी वरिष्ठता के अनुसार इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया, सिवाय इस निर्देश के कि अपीलकर्ता को ज्ञापन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सेवा में शामिल होना चाहिए और फिर यदि वह चाहे तो वरिष्ठता के लिए अपने मामले का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके बाद अपीलकर्ता ने उन्हें संपदा विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में फिर से नियुक्त करने के आदेश को स्वीकार कर लिया और अपने कार्यालय का कार्यभार संभाला। उच्च न्यायालय के आदेश में पाया गया कि अपीलकर्ता को छंटनी के कारण 1.10.1967 को सेवा से मुक्त कर दिया गया था।

जब अपीलकर्ता के मामले में उपरोक्त कार्यवाही हो रही थी तो कर्मचारी चयन समिति द्वारा उत्तरदाताओं 6 से 11 को सीधे जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में चुना गया और उक्त पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलकर्ता शायद ऊपर उल्लिखित विभिन्न कार्यवाहियों के कारण कर्मचारी चयन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वह 5.12.1962 से 13.5.1964 तक निलंबित रहा जब उसे हटा दिया गया और फिर 16.8.65 तक निलंबित कर दिया गया, जब उसे हटा दिया गया। उन्हें ड्राफ्ट्समैन के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। एक बार जब अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई, तो नगर आयुक्त ने आदेश पारित किया।

3.3.1971 को दिनांक 13.5.1964 के आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थी को सेवा से हटा दिया गया।उन्हें टाउनप्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इसके बाद, हालांकि, टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान को समाप्त कर दिया गया, और अपीलकर्ता को दिनांक 30.9.1976 का आदेश दिया गया, जिसके द्वारा उसे नगर निगम, निगम की सेवाओं में वापस कर दिया गया। हालाँकि, ऐसे रिवर्टर पर, जैसा कि हमने देखा है, उसे एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नहीं बल्कि एक ट्रेसर के रूप में तैनात किया गया था। अपीलकर्ता ने उक्त आदेश के खिलाफ स्थायी समिति के समक्ष अपील दायर की लेकिन उसकी अपील 15.3.1977 को इस आधार पर खारिज कर दी गई कि निगम में सीधी भर्ती वाले पहले से ही जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम कर रहे थे और जूनियर ड्राफ्ट्समैन का कोई पद खाली नहीं था। निगम, जिसमें अपीलकर्ता को नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की और, जैसा कि पहले ही कहा गया है, वह इसमें सफल रहा और इसलिए यह वर्तमान अपील है।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के दो तर्क थे।

पहला तर्क यह था कि चूंकि उन्हें दिनांक 21.4.1960 के आदेश द्वारा टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें नगर निगम में ट्रेसर के रूप में, यानी निचले पद पर वापस नहीं भेजा जा सकता था।

यह भी तर्क दिया गया कि आदेश दिनांक 30.9.1976 को उप नगर आयुक्त द्वारा पारित किया गया है, जो कि उसे नियुक्त करने वाले व्यक्ति, अर्थात् नगर निगम आयुक्त से अधिक रैंक का व्यक्ति है और इसलिए, आदेश दिनांक 30.9.76 को एक द्वारा पारित किया गया था। अधिकार क्षेत्र के बिना अधिकारी. ये दोनों तर्क हमारे सामने भी दोहराए गए हैं। जहां तक दूसरे विवाद का संबंध है, यह तुरंत बताया जा सकता है कि यदि दिनांक 30.9.76 का आदेश दंड के माध्यम से वापसी का आदेश है, तो अपीलकर्ता का तर्क बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम की धारा 53 और 56 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर सही हो सकता है। हालाँकि, यदि आदेश दिनांक 30.9.76 ने केवल प्रभाव डाला है। टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान को समाप्त कर दिया जाए और अपीलकर्ता को उस पद पर बहाल कर दिया जाए जिसे वह नगर निगम में उचित रूप से रख सकता है, तो प्रत्यावर्तन का कोई तत्व शामिल नहीं होगा और उपायुक्त प्रश्न में आदेश पारित करने में काफी सक्षम होगा। इसलिए विचार के लिए एकमात्र प्रश्न दिनांक 30.9.76 के आदेश की वैधता के संबंध में है, जहां तक इसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता को जूनियर ड्राफ्ट्समैन के बजाय नगर निगम में एक ट्रेसर के रूप में नियुक्त किया जाए। हम यहां उल्लेख कर सकते हैं कि एक मुद्दा यह भी उठाया गया था कि अपीलकर्ता को "अभिनय" अनुरेखक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन निगम द्वारा यह समझाया गया है कि यह एक मौखिक अशुद्धि थी और नगर निगम में अपीलकर्ता की नियुक्ति अभिनय नहीं बल्कि सारभूत है। अत: यह बात टिक नहीं पाती।

हम इस धारणा पर आगे बढ़ेंगे कि अपीलकर्ता नगर निगम से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान (जो एक अस्थायी था) में गया था। इस बात पर कुछ विवाद है कि क्या अपीलकर्ता को टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में उचित रूप से पदोन्नत किया गया था। एक सुझाव है कि टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान द्वारा अपीलकर्ता की सेवाओं के साथ-साथ उसकी पदोन्नति की मांग भी निगम को स्वीकार्य नहीं थी और यह मध्यस्थ द्वारा अपीलकर्ता को दिखाए गए अनुचित पक्ष का परिणाम था। नियुक्ति प्राधिकारी हमें नहीं लगता कि यहां इस विवाद में जाना आवश्यक है क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नति और नगर नियोजन प्रतिष्ठान में सर्वेक्षक सह ड्राफ्ट्समैन के रूप में प्रस्तावित पदोन्नति उसे उसके मूल विभाग में कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकती है। जब उन्होंने नगर निगम छोड़ा और टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में शामिल हुए तो वह एक ट्रेसर थे और वह संपत्ति विभाग या नगर निगम के किसी अन्य विभाग में केवल अपने मूल पद यानी ट्रेसर के रूप में वापस जा सकते हैं, संशोधन के अधीन, यदि में इस बीच वह एक उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त कर चुका है, उसे उस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में, दुर्भाग्य से, ऐसा हुआ कि जब 1959-60 और 1963-64 में नगर निगम द्वारा जूनियर ड्राफ्ट्समैन की भर्ती की गई, तो कर्मचारी चयन समिति की मशीनरी के माध्यम से उक्त पदों पर व्यक्तियों का चयन और नियुक्ति की गई।

अपीलकर्ता का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से नजरअंदाज किया गया था और उत्तरदाताओं को गलत तरीके से जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह बताते हैं कि, नियमों के तहत, कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन को वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाना था और कर्मचारी चयन समिति का सवाल ही नहीं उठता था। उनके अनुसार, जब भर्ती नगरपालिका सेवा में व्यक्तियों तक ही सीमित थी, तो कर्मचारी चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। हालाँकि, वर्तमान मामले में, सभी व्यक्ति, जिन्हें अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के दौरान जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया था, नगरपालिका सेवा से थे। इसलिए, नियुक्ति कर्मचारी चयन समिति की हस्तक्षेप मशीनरी के बिना सीधे पदोन्नति द्वारा की जानी चाहिए थी और अपीलकर्ता को सबसे वरिष्ठ ट्रेसर होने के नाते उत्तरदाताओं 6 से 11 की प्राथमिकता में कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए था।

अपीलकर्ता के इस मामले को स्वीकार करने में काफी कठिनाइयां हैं। सबसे पहले, वह वास्तव में जो प्रयास कर रहा है वह उत्तरदाताओं 6 से 11 की नियुक्तियों को चुनौती देना है जो कि 1978 में दायर एक रिट याचिका द्वारा 1963,64 में की गई थी, उपरोक्त चयन और नियुक्ति के एक दशक से भी अधिक समय बाद। यह सच है कि, उस समय अपीलकर्ता, संदेह के घेरे में था क्योंकि उसे निलंबित कर दिया गया था और बाद में सेवा से हटा दिया गया था। लेकिन फिर भी, अगर वह उन नियुक्तियों को चुनौती देना

चाहते थे तो उन्हें तत्काल कदम उठाना चाहिए था। किसी भी तरह, ये बाधाएँ तब गायब हो गईं जब ट्रिब्यूनल ने, उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड पर, आदेश दिनांक 13.5.1964 द्वारा अपीलकर्ता को सेवा से हटाने को अस्वीकार कर दिया था। कम से कम 1971 में, जब उन्हें टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के पद पर बहाल करने का आदेश पारित किया गया था, तो उन्हें मूल विभाग में "प्रो-फॉर्मा" पदोन्नति प्राप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए था। अपीलकर्ता का कहना है कि वह कुछ कर रहे थे अभ्यावेदन लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। तथ्य यह है कि 1963-64 से लेकर 15.2.1978 तक, जब उन्होंने रिट याचिका दायर की थी या कम से कम 1.10.1976 तक, जब उन्होंने प्रत्यावर्तन के आदेश के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया था, उत्तरदाताओं 6 से 11 की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए उन्होंने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।

उपरोक्त विचार के अलावा, हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उत्तरदाताओं 6 से 11 की नियुक्तियाँ अनियमित रूप से की गईं और जूनियर ड्राफ्ट्समैन के चयन के लिए कर्मचारी चयन समिति का गठन बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियमके नियमों और प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। निगम ने कहा है कि उनकी सीधी भर्ती की गयी है उच्च न्यायालय ने बताया है कि संबंधित विनियमन ने आयुक्त को सीधी भर्ती एस 54(2) नगरपालिका अधिनियम द्वारा नियुक्तियां प्रमोटर करने का विवेक दिया है, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि

जब यह प्रस्तावित किया जाता है तो कर्मचारी चयन समिति को छूट दी जाती है। पहले से ही नगरपालिका सेवा में कार्यरत व्यक्तियों में से नियुक्ति भरें लेकिन पुनर्नियुक्ति की प्रकृति ज्ञात नहीं है, इसके अलावा, चयन पर निर्णय लेने के लिए कर्मचारी चयन समिति के गठन को अवैध नहीं कहा जा सकता है, भले ही स्थिति में यह अनिवार्य नहीं है, उच्च न्यायालय ने एक तथ्य के रूप में पाया है निर्णय में एक से अधिक स्थानों पर कहा गया है कि उत्तरदाताओं 6 से 11 को कर्मचारी चयन समिति द्वारा उचित जांच के बाद सीधे जूनियर ड्राफ्टमैन का चयन किया गया था, यहां तक कि अपीलकर्ता ने हमारे सामने कहा था कि इन नियुक्तियों और चयनों के संबंध में नगरपालिका कर्मचारियों के बीच एक परिपत्र था।

अपीलकर्ता को उस समय चयन के लिए आवेदन करना चाहिए था या, यदि उसे लगता है कि यह अधिक उचित है तो उसे कर्मचारी चयन समिति के गठन और सीधी भर्ती को चुनौती देनी चाहिए थी और अपनी वरिष्ठता के आधार पर ज्यूपिटर ड्राफ्ट्समैन के रूप में पदोन्नति के लिए अपने दावे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। वह महत्वपूर्ण समय पर ऐसा करने में विफल रहे। ऐसा हो सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निलंबन और उसके बाद सेवा से निष्कासन के कारण उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 1971 में, उनके निलंबन और निष्कासन के मूल आदेश को रद्द कर दिए जाने के बाद भी, उन्होंने मूल विभाग में अपने अधिकारों का दावा करने के लिए तत्काल कोई कदम नहीं

उठाया। वह टाउन प्लानिंग प्रतिष्ठान में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में अपनी बहाली से स्पष्ट रूप से संतुष्ट थे। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि, उत्तरदाताओं 6 से 11 की नियुक्ति की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वह उनकी वरीयता में किसी भी पदोन्नति का हकदार नहीं था और जब ऐसा कोई पद नहीं था तो वह जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। 1976 में जिस पर उन्हें नियुक्त किया जा सका। यह उनका मामला नहीं है कि मूल विभाग में उनके वापस जाने के बाद जूनियर ड्राफ्ट्समैन का कोई पद खाली हो गया था, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जा सकता था।

अपीलकर्ता का तर्क है कि मूल विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी पात्रता को पहले उल्लिखित आदेश दिनांक 16.8.1965 द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह भी बताया गया है कि बाद में अपीलकर्ता और एक कावड़िया के बीच वरिष्ठता का सवाल उठा। इसे स्वीकार कर लिया गया और नगर निगम ने यह स्वीकार कर लिया कि अपीलकर्ता के पास जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं और वह श्री कावड़िया से वरिष्ठ हैं। यह 1966 में कुछ समय था। हालाँकि, हम पाते हैं कि मामले का यह पहलू अपीलकर्ता को मदद नहीं करता है क्योंकि दिनांक 16.8.1965 का आदेश औद्योगिक न्यायालय की सिफारिश के अनुसरण में पारित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को हटाने की मंजूरी दी गई थी, कि वह नियुक्ति हेतु पुनर्विचार किया जा सकता है। औद्योगिक

न्यायालय के इस आदेश के मद्देनजर, अपीलकर्ता को एक पोस्टिंग दी जानी थी और चूँकि जब वह जूनियर ड्राफ्ट्समैन था तब उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए उसे जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त करने के आदेश पारित किए गए थे। इसे फिर से नई नियुक्ति के आदेश के रूप में बनाया गया था और अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व कि उसे वरिष्ठता दी जानी चाहिए, ऊपर उल्लिखित कारण से स्वीकार नहीं किया गया था। एक और तथ्य यह भी है कि अपीलकर्ता को 1 अक्टूबर, 1967 से इस पद से मुक्त कर दिया गया था। जाहिर तौर पर, इस आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा, जब याचिकाकर्ता को नगर नियोजन प्रतिष्ठान में उसके पद पर बहाल कर दिया गया तो इन आदेशों ने अपना आधार खो दिया। इन परिस्थितियों में दिनांक 16.8.65 का आदेश या 1966 में अपीलकर्ता और कावड़िया के बीच वरिष्ठता का निर्धारण अपीलकर्ता के मामले में मदद नहीं करता है।

नगर निगम के विद्वान वकील ने हमें बताया कि अपीलकर्ता ने आदेश दिनांक 30.9.76 के अनुपालन में अनुरेखक के रूप में अपना पद ग्रहण नहीं किया है और अब तक वह सेवानिवृत्ति की आयु तक भी पहुंच चुका है। हम इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.9.76 के आदेश की "अस्वीकृति" के परिणामों से चिंतित नहीं हैं। हम केवल इस प्रश्न से चिंतित हैं कि क्या अपीलकर्ता को नगर निगम में उसके प्रत्यावर्तक पर अनुरेखक के रूप में उचित रूप से नियुक्त किया गया था। निगम और उस प्रश्न का

हमने सकारात्मक उत्तर दिया है। हम प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए, हम इस अपील को खारिज करते हैं लेकिन, इन परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

जी.एन.

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।